दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 14.02.2024
उदघोषित: 26.02.2024

आप.वि.वा. 2164/2022 और आप.वि.आ. 9155/2022

महदूम बावा बहरुद्दीन नूरुल ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री सिद्धार्थ खट्टर, श्री आकाश जैन और श्री डिविज एंडली, अधिवक्तागण

बनाम

कवेरी प्लास्टिक्स .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री अदिति पंचारिया, अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायाधीश श्री नवीन चावला

निर्णय

1. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के साथ पढ़ा गया है (संक्षेप में, "दं.प्र.सं.") जिसमें आपराधिक शिकायत संख्या 523804/2016 को रद्द करने की मांग की गई है, जिसका शीर्षक ***कावेरी प्लास्टिक बनाम नाफ्टो गज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** धाराओं के तहत पंजीकृत 138/141/142 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में, "एन. आई. अधिनियम"),

विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट, एन. आई. अधिनियम-04, केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (इसके बाद "महानगर मजिस्ट्रेट" के रूप में संदर्भित) के न्यायालय के समक्ष लंबित है।

<u>तथ्यात्मक मैट्रिक्स</u>

2. उपरोक्त शिकायत का मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को आरोपी सं.3. उक्त शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी सं.1, अर्थात्, नाफ्टो गज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ प्रत्यर्थी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया, जो कि शिकायतकर्ता है, 30.04.2012 पर, खसरा सं. 75, खेवट सं .61, खाता सं.112 और नई दिल्ली के अर्जुन नगर के अबादी में स्थित गाँव-हुमायूं पुर के खातोनी सं .61/14 ने अंतिम बिक्री विलेख के निष्पादन तक उक्त संपत्ति को पट्टे पर लेने पर भी सहमति व्यक्त की। इसने पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए किराए के भुगतान के दायित्व के लिए कुछ चेक भी जारी किए।

3. यह कहा गया है कि चेक सं. 876229 इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली पर दिनांकित 12.05.2012, आरोपी सं.1 द्वारा जारी की गई 1 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये) की राशि *'अपर्याप्त धन'* टिप्पणी के साथ अनादरित वापस कर दिया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि उक्त चेक के अनादर पर, प्रत्यर्थी ने 08.06.2012 पर एक कानूनी मांग नोटिस भेजा, जिस पर आरोपी

संख्या 4 और 5 ने गलत और तुच्छ जवाब दिया। आरोप है कि आरोपी सं .3/याचिकाकर्ता ने यहाँ मांग नोटिस की सेवा से परहेज किया।

4. शिकायत में अभियुक्त, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, को विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 04.09.2012 के आदेश द्वारा तलब किया गया था।

5. हालांकि वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है, याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

6. नोटिस तैयार करने के चरण में, याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त के साथ, आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि दिनांकित मांग के नोटिस में अभियुक्त को जारी किए गए चेक की दोगुनी राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था और इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के संदर्भ में नहीं था, और इस कारण से, शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं थी। हालाँकि, उक्त आवेदन को विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 06.10.2021 दिनांकित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि यह बनाए रखने योग्य नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है।

<u>याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन चेक 1 करोड़ रुपये की राशि का था, हालांकि, दिनांक 1 के मांग नोटिस द्वारा, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता से 2 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने की मांग की थी। के निर्णयों पर निर्भरता रखना उच्चतम न्यायालय ने ***सुमन सेठी बनाम अजय के. चुरीवाल और अन्य*** (2000) 2 एस. सी. सी. 380 और ***राहुल बिल्डर्स बनाम अरिहंत फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और अन्य,*** (2008) 2 एस. सी. सी. 321, वह प्रस्तुत करता है कि शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि चेक राशि से अधिक की मांग प्रत्यर्थी द्वारा मांग सूचना में की गई है।

8. वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी की याचिका कि 08.06.2012 दिनांकित कानूनी नोटिस में एक मुद्रण संबंधी त्रुटि थी, न केवल झूठी है, बल्कि शिकायत को बनाए रखने योग्य बनाने के लिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस गलती का लाभ, यदि कोई हो, तो आरोपी के पक्ष में होना चाहिए। जब तक चेक की राशि की मांग नहीं की जाती है, भले ही वह लिपिकीय गलती से हो, तब तक शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगा।समर्थन में, वह ***मैसर्स यांके ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड हैदराबाद बनाम मेसर्स सिटी बैंक*** 2001 एससीसी ऑनलाइन एपी 381; मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में ***छाबड़ा फैब्रिक्स प्राइवेट में बनाम भगवानदास, ढींगरा के मालिक; हस्तशिल्प*** 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 24809; केरल उच्च न्यायालय में

रामराज बनाम राजेश कुमार टी. एस., 2014; एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 7009; मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ***गोकुलदास बनाम अटल बिहार और अन्य,*** 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 1583; और कर्नाटक उच्च न्यायालय के ***के.गोपाल बनाम टी. मुकुंद,*** (निर्णय दिनांक 29.07.2021 दाण्डिक अपीलीय सं.1011/2010 में पारित) मामले का संदर्भ देखा जा सकता है।

9. वे प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी की यह दलील कि दिनांक 08.06.2012 के नोटिस में लिपिकीय गलती थी क्योंकि 2 करोड़ रुपये की राशि के लिए एक सहित एक से अधिक नोटिस प्रत्यर्थी द्वारा एक साथ जारी किए गए थे, गलत है, क्योंकि 2 करोड़ रुपये के चेक के अनादर के लिए नोटिस केवल 14.09.2012 को जारी किया गया था, यानी विचाराधीन नोटिस के तीन महीने से अधिक समय बाद।

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि दिनांकित 08.06.2012 कानूनी नोटिस में एक लिपिकीय गलती थी। वह प्रस्तुत करती है कि चूंकि आरोपी द्वारा एक से अधिक चेक जारी किए गए हैं। 1, चेक के अपमान पर एक से अधिक नोटिस एक साथ तैयार किए गए थे।गलती से, 2 करोड़ रुपये की राशि, जो एक अन्य चेक के संबंध में थी, का उल्लेख से संबंधित दिनांकित 08.06.2012 के नोटिस में मांग के रूप में किया गया था। 1 करोड़ रुपये का चेक, जो वर्तमान याचिका का विषय है। वह प्रस्तुत करती है

कि शिकायत वर्ष 2012 से निर्णय के लिए लंबित है, और इसलिए, इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। वह प्रस्तुत करती है कि नोटिस के बावजूद, याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्तों ने नोटिस तैयार करने के चरण तक उपरोक्त शिकायत नहीं उठाई। वह प्रस्तुत करती है कि चूंकि यह केवल एक लिपिकीय त्रुटि है, इसलिए याचिकाकर्ता को अपराध से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है।

12. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 निम्नानुसार है:

> *"138. खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर।—जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ रखे गए खाते से निकाला गया कोई भी चेक बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाता है, या तो इस कारण से कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या कि वह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान करने के लिए व्यवस्थित राशि से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 4 [एक अवधि जो दो साल तक बढ़ाई जा सकती है] के*

कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो चेक की राशि से दोगुनी हो सकती है, या दोनों के साथ:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि -

(क) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस दिन इसे तैयार किया गया है या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो;

(ख) प्रापक या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में, चेक के ड्रॉअर को एक नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; लिखित रूप में, बैंक से उसके द्वारा चेक के भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त होने के 5 [तीस दिनों के भीतर]; और

(ग) इस तरह के चेक का आहरणकर्ता उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, चेक के नियत समय में, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अन्य दायित्व के ऋण" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व।"

13. ***सुमन सेठी*** (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि मांग का नोटिस चेक की राशि का होना चाहिए।यदि चेक की राशि के अलावा, ब्याज या लागत के रूप में आगे की मांग की जाती है, तो यह नोटिस की भाषा पर निर्भर करेगा कि क्या यह कानूनी रूप से खराब है। जहां एक सर्वव्यापी मांग यह निर्दिष्ट किए बिना की जाती है कि असम्मानित चेक के तहत क्या देय

था, तो नोटिस कानूनी आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> *"**8.** यह कानून का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि नोटिस को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। नोटिस में, "उक्त राशि" यानी चेक राशि की मांग की जानी चाहिए।यदि ऐसी कोई मांग नहीं की जाती है तो कोई संदेह नहीं है कि नोटिस इसकी कानूनी आवश्यकता से कम होगा। जहाँ "कथित राशि" के अलावा ब्याज, लागत आदि के रूप में भी दावा किया जाता है कि क्या नोटिस खराब है यह नोटिस की भाषा पर निर्भर करेगा।यदि किसी सूचना में दावे का विवरण देते समय चेक राशि, ब्याज, हर्जाना आदि अलग से निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो ब्याज, लागत आदि के लिए ऐसे अन्य दावे अनावश्यक होंगे और ये अतिरिक्त दावे अलग किए जा सकते हैं और सूचना को अमान्य नहीं करेंगे। हालाँकि, यदि नोटिस में यह निर्दिष्ट किए बिना एक सर्वव्यापी मांग की जाती है कि असम्मानित चेक के तहत क्या देय था, तो नोटिस कानूनी आवश्यकता को पूरा करने में विफल हो सकता है और इसे खराब माना जा सकता है।"*

14. उपरोक्त विचार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***राहुल बिल्डर्स*** (पूर्वोक्त) में दोहराया गया था, जिसमें कहा गया था:-

> *"**10**. एक शिकायत को बनाए रखने के लिए एक नोटिस की सेवा, यह तुच्छ है, चरित्र में अनिवार्य है। यह एक कानूनी कल्पना पैदा करता है। अधिनियम की धारा 138 का संचालन परंतुक द्वारा सीमित है। जब परंतुक लागू होता है, तो मुख्य खंड लागू नहीं होगी। जब तक अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अनुरूप कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तब तक शिकायत याचिका विचारणीय नहीं होगी। संसद ने उक्त*

प्रावधान को लागू करते समय जानबूझकर कुछ शर्तें लगाई थीं। शर्तों में से एक चेक की राशि के भुगतान की मांग करने वाले नोटिस की सेवा थी जो "उक्त राशि का भुगतान" वाक्यांश के उपयोग से स्पष्ट है। इस तरह की सूचना भुगतान न किए गए चेक की वापसी के संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 30 (एस. आई. सी. 15) दिनों की अवधि के भीतर जारी की जानी चाहिए।अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने की परिकल्पना की गई है। एक दंडात्मक प्रावधान का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए; पूर्ववर्ती शर्त जिसके लिए नोटिस की सेवा है। यह कहना एक बात है कि मांग न केवल चेक के तहत अवैतनिक राशि का प्रतिनिधित्व कर सकती है, बल्कि लागत और ब्याज जैसे अन्य आनुषंगिक खर्चों का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि सूचना अस्पष्ट और में सक्षम होगी। व्याख्याएँ। अनादरित चेक के तहत देय राशि के बारे में निर्दिष्ट किए बिना एक सर्वव्यापी सूचना कानून की आवश्यकता को कम नहीं करेगी।प्रत्यर्थी सं. 1 को उस राशि का भुगतान करने के लिए नहीं कहा गया था जो उसके द्वारा जारी किए गए चेक के तहत देय थी। जिस राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, वह बिलों की बकाया राशि थी यानी 8,72,409 जिसमें नोटिस प्राप्तकर्ता को उक्त मांग का जवाब देना था। इसके अनुसार, इसे 8,72,409 रुपये की पूरी राशि की पेशकश करनी थी। उस पर 1,00,000 की उक्त राशि का भुगतान करने की कोई मांग नहीं की गई थी, जिसे शिकायतकर्ता को दिनांक 30-4-2000 के चेक द्वारा दिया गया था।इसलिए जो मांग की गई थी वह पूरी राशि थी न कि उसका हिस्सा।"

15. इस संबंध में इस निर्णय का भी उल्लेख किया गया है। ***मैसर्स एलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम विनय मित्तल,*** 2010

एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 182, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:-

> *"**12.** … … ……मेरे विचार से, इस प्रकार के मामले में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (ख) में उपयोग की गई "धन की राशि" का अर्थ होगा चेक के द्वारा प्राप्तकर्ता को वास्तव में प्रदत देय राशि। बेशक, यदि चेक का प्राप्तकर्ता ब्याज, मुआवजे, आकस्मिक खर्च आदि के कारण कुछ मांग करता है, तो यह नोटिस को तब तक अमान्य नहीं करेगा जब तक कि चेक के प्राप्तकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राशि सही है और नोटिस में स्पष्ट रूप से पहचानी गई है। जब मांग की सूचना में दावा की गई मूल राशि चेक के प्राप्तकर्ता को वास्तव में देय मूल राशि से अधिक है और सूचना भी अतिरिक्त राशि की मांग के लिए आधार का संकेत नहीं देती है, तो इस तरह की सूचना को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (ख) में परिकल्पित कानूनी और वैध सूचना नहीं कहा जा सकता है। ऐसे मामले में, यह खुला नहीं है। शिकायतकर्ता को यह याचिका दायर करने के लिए कि चेक का ड्रॉअर चेक के प्राप्तकर्ता को अपनी ओर से देय वास्तविक राशि का भुगतान करके दायित्व से बच सकता था। नोटिस को वैध और मान्य बनाने के लिए, इसे अनिवार्य रूप से चेक के प्राप्तकर्ता को देय मूल राशि को निर्दिष्ट करना चाहिए और चेक के माध्यम से आदेशित मूल राशि उसके द्वारा देय वास्तविक राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, हालांकि नोटिस में कुछ अन्य आदेशों को जोड़ने से ऐसा नोटिस अवैध या अमान्य नहीं होगा।"*

16. इसलिए एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) को ध्यान में रखते हुए, शिकायत दर्ज करने के लिए वाद हेतुक कारण शिकायतकर्ता को केवल तभी प्राप्त होगा जब शिकायतकर्ता चेक की वापसी के बारे में

शिकायतकर्ता द्वारा बैंक से जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक के दराज को लिखित रूप में नोटिस देकर "उक्त राशि" के भुगतान की मांग करता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) में उल्लिखित "उक्त राशि" चेक राशि है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि ऐसी कोई मांग नहीं की जाती है, तो नोटिस कानूनी आवश्यकता से कम होगा।यह आगे स्पष्ट किया गया है कि यदि नोटिस में कोई अतिरिक्त दावे भी किए जाते हैं, जब तक कि वे प्रकृति में अलग नहीं होते हैं, तो शिकायत दर्ज करने के लिए वाद हेतुक कारण विफल हो जाएगा।इस संबंध में उच्चतम न्यायालय साथ ही ***दशरथभाई त्रिकंभाई पटेल बनाम हितेश महेंद्रभाई पटेल और अन्य*** (2023) 1 एस. सी. सी. 578, के फैसले का भी संदर्भ दिया जा सकता है।

17. वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, 08.06.2012 दिनांकित मांग के नोटिस में इसने अतिरिक्त राशि 1 करोड़ की मांग करने के बजाए राशि 2 करोड़ की मांग का कारण भी नहीं बताया। इसलिए, उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, नोटिस एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान (ख) के अनुपालन में नहीं था।

18. जहाँ तक प्रत्यर्थी के विद्वत वकील का यह निवेदन है कि नोटिस में टंकण संबंधी त्रुटि थी, हालाँकि याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने इस बात पर जोर देकर विवाद किया है कि विचाराधीन नोटिस के साथ-साथ प्रत्यर्थी द्वारा 2

करोड़ रुपये की राशि से संबंधित चेक के लिए कोई अन्य नोटिस जारी नहीं किया गया था, इस न्यायालय को इस स्तर पर इस विवाद में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आपराधिक दायित्व को जन्म देती है। इसलिए इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसे लागू करने की शर्त का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

19. ***गौकुलदास*** (पूर्वोक्त) में, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को वास्तव में उस स्थिति का सामना करना पड़ा था जहां चेक राशि रु.4,30,000/- थी हालाँकि, एक टंकण संबंधी त्रुटि के कारण, नोटिस में केवल रु.43,000/-, यानी कम राशि की मांग की गई थी। इसके बावजूद, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए शिकायत को रद्द कर दिया:

> *"20. केवल यह कहकर कि वैधानिक सूचना में इस प्रकार उल्लिखित राशि टंकण संबंधी त्रुटि के कारण गलत थी, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, शिकायतकर्ता परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (ख) के तहत उसके द्वारा जारी किए गए सूचना से छुटकारा नहीं पा सकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान दंडात्मक प्रकृति के हैं और इसलिए, प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।"*

20. इसी तरह, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ***मैसर्स यांके पेज ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड हैदराबाद*** (पूर्वोक्त) का सामना किया गया था। इस तथ्य के साथ कि हालांकि बैंक द्वारा अनादर किया गया चेक 9,972/- रुपये का था, लेकिन नोटिस में केवल 3,871/- रुपये की मांग की गई थी। इस

विसंगति को फिर से एक टंकण संबंधी त्रुटि के रूप में समझाने की कोशिश की गई। हालाँकि, शिकायतकर्ता के उक्त निवेदन को अदालत ने निम्नानुसार देखते हुए खारिज कर दिया था:

> *"**15**. मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, नोटिस देना और अनादरित चेक द्वारा कवर की गई राशि के भुगतान की मांग करना अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के मुख्य घटकों में से एक है। यदि वह मुख्य घटक गायब है, तो धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं माना जाता है। इसके अलावा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एच. एल. अग्रवाल बनाम राकेश अग्रवाल, 1997 (1) ए. एल. टी. (आप.) 678 में पहले ही कहा जा चुका है, अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध "एक तकनीकी अपराध है" अधिनियम की धारा 138 के तहत विचार की गई सभी तकनीकी औपचारिकताओं का पालन किया जाना चाहिए।*
>
> ***16.** उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि प्रथम प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत, प्रथमदृष्टया अधिनियम की धारा 138 के तहत एक अपराध का खुलासा करने में विफल रही। इसलिए याचिकाकर्ता-अभियुक्त पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना होगा।"*

21. ***छाबड़ा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में, उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा को इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया गया कि अनादर किए गए चेक की संख्या में विसंगति थी। टाइपोग्राफिक त्रुटि का आरोप लगाकर इसे फिर से समझाने की कोशिश की गई। हालाँकि, न्यायालय ने शिकायतकर्ता के उक्त निवेदन को निम्नानुसार टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया:

*"**7.** निर्विवाद रूप से, दोनों पक्षों के पास थाहथकरघा के संबंध में एक-दूसरे के साथ व्यापारिक लेन-देन।यह रिकॉर्ड में आया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को सुरक्षा चेक के रूप में चेक सं .476844 जारी किया था, जिसे उसने ₹3,26,565.51 के लिए बिल सं.248 दिनांकित 25/09/1995 के लिए आंशिक भुगतान के रूप में ₹4 की राशि भरकर नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया था, लेकिन ऋण लेने वाले बैंक द्वारा धन की व्यवस्था न करने के कारण इसका अनादर किया गया था।हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से, शिकायतकर्ता ने आरोपी को एक कानूनी नोटिस दिया, जिसका दिनांक 26/09/1995 था, जो स्पष्ट रूप से विवादग्रस्त चेक के लिए नहीं था।यह सच हो सकता है कि चेक संख्या टाइप करते समय उक्त कानूनी सूचना में मुद्रण संबंधी त्रुटि थी, लेकिन इस तरह की मुद्रण संबंधी त्रुटि, यदि कोई हो, तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अनिवार्य प्रावधानों के अनुपालन को पूरा नहीं करती है और शिकायतकर्ता के लिए एकमात्र रास्ता आरोपी को एक नया कानूनी सूचना देना था जो स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान मामले में नहीं किया गया है और इसलिए यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित है कि अधिनियम की धारा 138 के अनिवार्य प्रावधानों के वैधानिक अनुपालन के अभाव में, वर्तमान शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है।निचली अदालत ने मामले के उक्त पहलू की सराहना की और सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है और इस प्रकार उसके द्वारा दायर शिकायत को खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।"*

22. केरल उच्च न्यायालय ने ***रामराज*** (पूर्वोक्त) मामले में एक बार फिर केवल चेक की राशि का दावा करने के लिए नोटिस की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा:

> *"**10**. एक वैध अभियोजन यू/एस में।138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार, मेरा विचार है कि शिकायत को बनाए रखने के लिए नोटिस देना अनिवार्य है। संसद ने धारा 138 को लागू करते समय एक शर्त लगाई कि, चेक के भुगतान की मांग करते हुए लिखित में सूचना देकर राशि देना आवश्यक है। इस तरह की सूचना वैधानिक अवधि के भीतर जारी की जानी चाहिए। सशर्त उदाहरण चेक की राशि की मांग करना है। अनादरित चेक राशि से बड़ी राशि की मांग करने वाला नोटिस आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। अनुलग्नक-III में देय राशि के रूप में रूपये 80 लाख की राशि का उल्लेख किया गया था, लेकिन वास्तव में उधार ली गई राशि केवल 8 लाख रुपये है। इसलिए, एन. आई अधिनियम की धारा 138 (ख) के अनुसार प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी। जब तक एन. आई अधिनियम 138 (ख) के साथ सहमति में कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, तब तक शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगी। वर्तमान मामले में, चेक राशि के भुगतान के लिए कोई मांग नहीं की गई थी। यदि अनुलग्नक-III नोटिस के साथ मुकदमा चलाया जाता है, तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।"*

23. कर्नाटक उच्च न्यायालय को, ***के गोपाल*** *(पूर्वोक्त)* में, फिर से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां हालांकि जिन चेकों का अनादर किया गया था, वे रुपये 2,00,000/- की राशि के थे-प्रत्येक के लिए, कानूनी नोटिस में रु.10,00,000/- की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा फिर से इसे टाइपोग्राफिक त्रुटि के रूप में समझाने की मांग की गई थी। हालाँकि, अदालत ने माना कि नोटिस दोषपूर्ण था, जिससे आरोपी को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध से बरी किया जा सकता है।

24. उपरोक्त से, यह स्पष्ट होगा कि नोटिस में टाइपोग्राफिक त्रुटि होने की प्रत्यर्थी की याचिका, भले ही तथ्यों पर स्वीकार की गई हो, कानूनी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती है ताकि प्रत्यर्थी को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत बनाए रखने के लिए वाद हेतुक कारण दिया जा सके। नोटिस दोषपूर्ण होने के कारण, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए वाद हेतुक कारण प्रत्यर्थी के पक्ष में नहीं था।

25. प्रत्यर्थी की दलील है कि चूंकि शिकायत रही है लंबे समय से लंबित इस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिकायत को रद्द करने के लिए पी. सी. को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को किसी शिकायत का बचाव करने की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ सकता है, जो इसके बावजूद बनाए रखने योग्य नहीं है।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत का मामला, यानी आपराधिक शिकायत सं. 523804/2016, जिसका शीर्षक ***कावेरी प्लास्टिक बनाम नाफ्टो गज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** है। याचिकाकर्ता के खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धाराओं 138/141/142 के तहत पंजीकृत को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

27. याचिका को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है। लागत के बारे में कोई आदेश जारी नहीं होगा।

न्या. नवीन चावला

26 फरवरी, 2024
आरएन/आरपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*